



भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India
आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय / Andhra Pradesh Regional Office
लेखा बजट एवं समन्वयन कक्ष / Audit, Budget & Co-ordination Cell

बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - वर्ष 2026-27 के 01 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय (एपी आरओ) के लिए समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

ई-निविदा संख्या: [आरबीआई/आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/1/26-27/ईटी/205](#)

उपर्युक्त निविदा के लिए 05 अगस्त 2026 को सुबह 11:00 बजे तुंगभद्रा सम्मेलन कक्ष, पहली मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, स्टालिन सेंट्रल, गवर्नर पेट, विजयवाड़ा - 520002 में पूर्व-बोली बैठक आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों की सूची नीचे दी गई है:

(क) बैठक में भाग लेने वाले बैंक के अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री कृष्ण कुमार एस	उप महाप्रबंधक
2.	श्रीमती रूपा वी.सी.	सहायक महाप्रबंधक
3.	श्री बेशता हरीश	प्रबंधक
4.	श्री हरिनाथ रेड्डी	सहायक प्रबंधक

(ख) बैठक में भाग लेने वाले चार्टर्ड अकाउंट फर्म के प्रतिनिधियों की सूची

क्र. सं.	फर्म का नाम	प्रतिनिधियों के नाम
1	जेआरएस एंड एसोसिएट्स	श्री एन रवि तेजा
2	आर एस एन एल एंड एसोसिएट्स	श्री जी. ईश्वर कुमार
3	चौधरी एंड राव	श्री एम एन विष्णु मोहन
4	पी सुब्बारायुडु एंड कंपनी	श्री बी राम चरण नायक
5	एम. एन. राव एंड एसोसिएट्स एलएलपी	श्री टी एस राम मोहन राव श्री वाई चैतन्य कृष्ण
6	कोमांदूर एंड कंपनी एलएलपी	श्री पी सुरेन्द्रनाथ राव
7	आरएसएम एंड एसोसिएट्स	श्रीमती ए सुनीता देवी

2. श्री कृष्ण कुमार एस, उप महाप्रबंधक ने बैठक में प्रतिभागियों का स्वागत किया। प्रबंधक श्री बेशता हरीश ने समवर्ती लेखा परीक्षकों की भूमिका के बारे में संक्षेप में बताया और निविदा दस्तावेज के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों पर प्रकाश डाला। इसके बाद, प्रतिभागियों से निविदा के संबंध में प्रश्न आमंत्रित किए गए थे। फर्मों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए प्रश्न और बैंक के स्पष्टीकरण नीचे सारणीबद्ध हैं।



क्रम संख्या	सवाल	बैंक का स्पष्टीकरण
i.	फर्मों ने सूचित किया कि उन्हें एमएसटीसी पोर्टल पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) को सत्यापित करते समय त्रुटियों का सामना करना पड़ रहा था।	यह स्पष्ट किया गया कि कंपनियां आवश्यक सहायता के लिए एमएसटीसी पोर्टल के अधिकारियों से संपर्क कर सकती हैं। एमएसटीसी के अधिकारियों के संपर्क विवरण पहले ही निविदा दस्तावेज में प्रदान किए जा चुके हैं। इसके अलावा, बैठक के दौरान एमएसटीसी से आवश्यक सहायता के लिए संबंधित एमएसटीसी अधिकारियों के संपर्क नंबर फर्मों के साथ साझा किए गए थे।
ii.	एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजों को अपलोड करने से संबंधित निविदा दस्तावेज के पृष्ठ 52 के संबंध में, फर्मों ने पोर्टल द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक फाइल का आकार होने की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में पूछताछ की।	यह स्पष्ट किया गया कि फर्मों को एमएसटीसी पोर्टल द्वारा अनुमत अधिकतम फाइल आकार के भीतर दस्तावेजों को अपलोड करना चाहिए। यदि फाइल आकार प्रतिबंधों के कारण कोई दस्तावेज अपलोड नहीं किया जा सकता है, तो फर्म आरबीआई के अधिकारियों से संपर्क कर सकती है और अतिरिक्त दस्तावेजों को ईमेल के माध्यम से बैंक को अग्रेषित कर सकती है। प्रति ईमेल अनुमत अधिकतम फाइल आकार 10 एमबी है, और यदि आवश्यक हो तो कई ईमेल भेजे जा सकते हैं।
iii.	फर्मों ने राय व्यक्त की कि निविदा में निर्दिष्ट 61,000 रुपये का न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक कम था और सुझाव दिया कि आरबीआई चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म द्वारा तैनात कर्मचारियों के आधार पर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए आईसीएआई मानदंडों को अपनाने पर विचार कर सकता है।	यह स्पष्ट किया गया कि, जैसा कि निविदा दस्तावेज के पृष्ठ 26 पर निर्दिष्ट है, ₹61,000/- प्रति माह न्यूनतम बोली राशि है, और इस सीमा से नीचे की राशि का हवाला देने वाली बोलियों को गैर-उत्तरदायी और अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। बोलीदाता अपने स्वयं के मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय रूप से व्यवहार्य राशि उद्धृत करने के लिए स्वतंत्र हैं। तकनीकी और वित्तीय बोलियों को क्रमशः 70 प्रतिशत और 30 प्रतिशत वेटेज देकर अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा और उच्चतम संयुक्त स्कोर प्राप्त करने वाले बोलीदाता को नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन के लिए सौंपे गए उच्च वेटेज को देखते हुए, अंतिम चयन केवल न्यूनतम वित्तीय बोली को उद्धृत करने पर निर्भर नहीं करेगा।
iv.	यह पूछताछ की गई थी कि क्या ऐसी फर्में जिनका पंजीकृत कार्यालय किसी अन्य राज्य में है, लेकिन जिनका शाखा	यह स्पष्ट किया गया कि यह एक सीमित निविदा है और केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लिए आईसीएआई के साथ पंजीकृत श्रेणी-I चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म ही भाग लेने के

	कार्यालय विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में है, वे बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हैं।	पात्र हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर की जाती है और यह राज्य के भीतर पंजीकृत पात्र श्रेणी-I फर्मों तक ही सीमित है।
v.	एसआई के संबंध में फर्म द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रमाणित दस्तावेजों की संख्या 10 (ii) यानी, कुशल कर्मचारियों को जारी किए गए नियुक्ति पत्र - आईपीसीसी के समूह II में योग्य) फर्मों ने वैकल्पिक दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में पूछताछ की जो प्रस्तुत किए जा सकते हैं जहां मूल नियुक्ति पत्र या तो अनुपलब्ध थे या नियुक्ति के समय जारी नहीं किए गए थे। यह भी सुझाव दिया गया था कि आईसीएआई फर्म कार्ड, भुगतान रिकॉर्ड या इसी तरह के दस्तावेजों को फर्म के साथ आर्टिकल असिस्टेंट के जुड़ाव और प्रासंगिक अवधि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। एक फर्म ने यह भी सुझाव दिया कि निविदा की प्रतिस्पर्धी प्रकृति को देखते हुए एक फर्म द्वारा नियुक्त भागीदारों, सहयोगियों और आर्टिकल सहायकों की संख्या के बारे में दस्तावेजी साक्ष्यों को सत्यापित किया जाना चाहिए। एक कंपनी ने सुझाव दिया कि रिजर्व बैंक आंकड़ों के सत्यापन के लिए ऑडिट फर्मों को जारी किए गए कैग स्कोर कार्ड या आईसीएआई के आंकड़ों का भी हवाला दे सकता है।	यह स्पष्ट किया गया कि आरबीआई फर्म से जुड़े आईपीसीसी के समूह II में योग्य कुशल कर्मचारियों की संख्या स्थापित करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का सत्यापन करेगा। कोई भी दस्तावेजी सबूत जो फर्म के साथ एक लेखबद्ध सहायक के जुड़ाव को संतोषजनक ढंग से स्थापित करता है, उस पर विचार किया जाएगा। बैंक फर्म के कर्मचारियों की संख्या के समर्थन में प्रस्तुत सभी दस्तावेजी साक्ष्यों को सख्ती से सत्यापित करेगा और जहां भी आवश्यक समझा जाए, अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग कर सकता है।
vi.	पृष्ठ 36, बिंदु 16 के संबंध में जिसमें कहा गया है कि "फर्म निर्दिष्ट अंतराल पर बैंक के जीएसटी और आयकर रिटर्न (और कोई अन्य संबंधित रिटर्न जो बाद में लागू हो सकती है) तैयार करेगी और दाखिल करेगी। क्या फर्म दाखिल करने या दाखिल करने से पहले	यह स्पष्ट किया गया था कि लेखा परीक्षकों को पूर्व-भुगतान (मंजूरी के बाद) और भुगतान के बाद दोनों चरणों में प्राप्त और कटौती किए गए करों की शुद्धता की समीक्षा और सत्यापन करने की आवश्यकता होगी। फर्म को बैंक के जीएसटी और आयकर रिटर्न के मसौदे को सत्यापित करने की आवश्यकता होगी (और कोई अन्य संबंधित रिटर्न जो बाद में लागू हो

	केवल रिटर्न की जांच करने के लिए जिम्मेदार होगी?	सकता है)। फर्म को समय सीमा के भीतर कार्यालय की ओर से लागू आईटी और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होगी। रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक डेटा को समेकित किया जाएगा और कार्यालय के निर्दिष्ट अनुभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा।
vii.	समवर्ती लेखा परीक्षक/सांविधिक केंद्रीय/शाखा लेखा परीक्षक के रूप में बैंक ऑडिट में सीए फर्म के अनुभव के लिए आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण का उल्लेख करते हुए, फर्मों ने कहा कि उनके पास संबंधित ऑडिट की गई फर्मों से प्रतिक्रिया के साथ अनुभव पत्र नहीं हैं। उन्होंने पूछताछ की कि क्या बैंकों द्वारा जारी किए गए नियुक्ति पत्र अनुभव प्रमाण पत्र के बदले स्वीकार किए जाएंगे।	यह स्पष्ट किया गया था कि निविदा दस्तावेज के अनुसार, संबंधित ऑडिट की गई फर्मों से फीडबैक के साथ अनुभव पत्र अपलोड किए जाने चाहिए। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां बैंकों द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं, संबंधित बैंकों द्वारा उनके आधिकारिक लेटरहेड पर जारी किए गए नियुक्ति पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे।
viii.	फर्मों ने समवर्ती लेखा परीक्षा करने के लिए कर्मियों की तैनाती के बारे में पूछताछ की।	यह स्पष्ट किया गया था कि, निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों के अनुसार, चयनित सीए फर्म को समवर्ती लेखा परीक्षा के लिए दैनिक आधार पर तीन कर्मियों को तैनात करना होगा, जिनमें से एक (1) योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट और दो कुशल कर्मचारी होने चाहिए। कुशल कर्मचारियों को आईपीसीसी (एकीकृत व्यावसायिक क्षमता पाठ्यक्रम) के सीए इंटरमीडिएट या ग्रुप II के कम से कम ग्रुप II उत्तीर्ण होना चाहिए और वर्तमान में लेखा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तैनात कर्मचारी भारतीय रिज़र्व बैंक के सामान्य कार्य घंटों के दौरान कार्यालय में उपस्थित होंगे। यह भी कहा गया था कि यदि संविदा की अवधि के दौरान भविष्य में कार्यालय को अमरावती में स्थानांतरित किया जाता है, तो नए स्थान पर उतनी ही संख्या में कर्मियों को तैनात किया जाना होगा।



3. फर्मों को यह भी सूचित किया गया कि वे एमएसटीसी पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/eprocn/index.jsp>) में किसी भी अंतिम मिनट की त्रुटि से बचने के लिए बोली लगाने की अंतिम तिथि से पहले निविदा दस्तावेजों को अपलोड करने का प्रयास करें। फर्मों को यह भी सूचित किया गया था कि सफल निविदाकर्ता के अलावा सभी निविदाओं के ईएमडी को सफल निविदाकर्ता को संविदा देने पर वापस कर दिया जाएगा। यह भी बताया गया कि ईएमडी भुगतान विवरण ईमेल के माध्यम से आरबीआई के अधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा। यदि फर्म एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत एक पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यम है, तो एमएसई प्रमाणपत्र की एक प्रति ईमेल के माध्यम से आरबीआई के साथ साझा की जाएगी।
4. बोलीदाताओं को ध्यान देना चाहिए कि निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए विवरण के साथ बोली-पूर्व बैठक के दौरान बैंक द्वारा प्रदान किए गए उपरोक्त सभी स्पष्टीकरण निविदा/संविदा का हिस्सा होंगे।
5. बैठक दोपहर 12:00 बजे संपन्न हुई।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
(आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय)